

20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज कोरोना संकट के इस काल में देश को आत्म-निर्भर बनाने के संकल्प के साथ सभी पक्षों से बातचीत के बाद तैयार हुआ है : निर्मला सीतारमण



बिंग ब्रेकिंग

NEWS
TODAY
ब्रेकिंग न्यूज़

www.newsupdate.in

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घास को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह पैकेज तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य में तेजी लाने के लिए यह पैकेज जरूरी था। उन्होंने अपने प्रेस सेट की शुरुआत आत्म-निर्भर बनाने के साथ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एनपीए हैं और जो लॉकडाउन के बालते परेशानी में हैं उन्हें इस कदम से फायदा होगा। 45 लाख एमएसएमई को राहत, एक साल तक कर चुकाने से मुक्ति मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा जिसमें 6 एमएसएमई के लिए कदम उठाएंगे दो कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है और 2 पीएफ से जुड़े हैं। एमएसएमई में डाला जाएगा।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम व लॉकडाउन के लिए 20 हजार करोड़ का प्राविधान। वहीं 50000 करोड़ का फॉन्ड एमएसएमई में डाला जाएगा।

बजट के फॉन्ड बाद कोरोना आ गया। बजट सेशन के बाद हमने गरीब कल्याण योजना के तहत 41 करोड़ खातों में पैसा पहुंचा था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी राशन दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मोदी सरकार लोगों से बातचीत और संवेदनशीलता में भरोसा रखती है और बजट के बाद तुरंत कोरोना का प्रकोप आगया।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने सबसे पहला कदम देश के गरीबों को लेकर उठाया। एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने सबसे पहला कदम देश के गरीबों को लेकर उठाया। एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने का उसने देश के लोगों में नई जरूरत भर रही है। लोग संकट में अवसर देख रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का लेखोंखा दे रही है। उन्होंने कहा कि कई मंत्रालयों की लंबी चर्चा के बाद पैकेज पर फैसला हुआ है। इस पैकेज के सहारे देश को आत्म निर्भर भारत कोहा जा रहा है। हम जो भी योजनाओं का ऐलान करेंगे वो नींधे लोगों तक पहुंचेंगे। गरीबों के खाते में सीधे पैसा पहुंच रहा है।

पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी, 2000 करोड़ से वेंटीलेटर तो 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर किए जाएंगे खर्च



ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि से 2000 करोड़ से वेंटीलेटर खरीदे जाएंगे जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मद में निर्धारित 3100 करोड़ में शेष 100 करोड़ की राशि कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर खर्च की जाएगी।

पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर तेज हो रही राजनीति के बीच सरकार ने पीएम केयर्स फंड से उनके आवागमन, खानान, चिकित्सा जैसी जलरतों को पूछा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। राज्यों को दिया गया यह फॉन्ड जिताधिकारी और निगम आयकृत के अधीन रहेगा। राज्यों में सरकारी तरफ से चलाए जा रहे कांडिल स्पैशल हॉस्पिटल में भारतीय में निर्मित 50 हजार वेंटीलेटर की आपूर्ति के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वैक्सीन विकास के लिए जारी फंड का उपयोग प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में होगा।

17 मई के बाद चौथे चरण के लॉकडाउन : 4.0 में ज्यादा छूट का संकेत, कोई सख्त लॉकडाउन तो कोई आर्थिक गतिविधियां युरु करना चाहता है

कोरोना के प्रसार की गति को कम करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। मंगलवार को रास्ते के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हट गया। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज्यादा छूट का संकेत भी दिया था। अधिकारियों के मुताबिक असीमी राशन की तरफ से चलाए जा रहे कांडिल

अधिकारियों का कलना है कि अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पांचियां रहेंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में हो सकती रखी जाएंगी। यहां तक कि रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और वशें की दुकानों की खोलने की अनुमति निलंबित करनी है। हालांकि अभी रेड जोन में बाजारों को फैसला भी राज्य सरकार के लिए नहीं है।

अधिकारियों का कलना है कि अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पांचियां रहेंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में हो सकती रखी जाएंगी। यहां तक कि रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और वशें की दुकानों की खोलने की अनुमति निलंबित करनी है। हालांकि अभी रेड जोन में बाजारों को फैसला भी राज्य सरकार के लिए नहीं है।

अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को जारी रखना चाहते हैं। इनमें से कुछ राज्य जोन तय करने का अधिकार अपने हाथ में चाहते हैं। राज्यों का यह अनुरोध माना जा सकता है, ताकि राज्य जमीनी हालात के आधार पर किसी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही या आधिक गतिविधियों को लेकर फैसला कर सकें। अभी कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करना चाहते हैं।

रेलवे और घरेलू उड़ानों के मामले में भी आगे हटे से कुछ अतिरिक्त अनुमति निलंबित की जाएगी। हालांकि अभी रेल और हवाई जहाज का परिवालन पूरी तरह शुरू होने में वक्त लग सकता है। विहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्य कम से कम मई अंत तक इन सेवाओं को पूरी तरह बालू करने के पक्ष में नहीं हैं।

सीमित यातायात की उमीद

लॉकडाउन के अगले चरण में कंटेनमेंट एरिया के अलावा सभी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं भी सीमित क्षमता के साथ शुरू की जा सकती हैं। सीमित सावधियों के साथ अंटी-ऑपरेटर्स के लिए एक अंडे-इवन फॉर्मूला अपना सकती है। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जा चुकी है।

क्या चाहते हैं राज्य?

सभी जारा कोरोना मरीजों वाले महाराष्ट्र की सरकार मुंबई, इसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में सख्त लॉकडाउन चाहते हैं। दूसरे सभी जारी कोरोना मरीजों वाला गुजरात बड़े शहरों के कंटेनमेंट में आर्थिक गतिविधियों शुरू करना चाहती है। करेल की सरकार रेस्टोरेंट और होटल भी खोलना चाहती है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामलों में बढ़ोत्तरी का सामना कर रहे विहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिवधि के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं।

आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़

20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्या मिला? जानें-वित्त मंत्री की बड़ी बातें



ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घास को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह पैकेज तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य में तेजी लाने के लिए यह पैकेज जरूरी था। उन्होंने अपने प्रेस सेट की शुरुआत आत्म-निर्भर बनाने के साथ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एनपीए हैं और जो लॉकडाउन के बालते परेशानी में हैं उन्हें इस कदम से फायदा होगा। 45 लाख एमएसएमई को राहत, एक साल तक कर चुकाने से मुक्ति मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा जिसमें 6 एमएसएमई के लिए कदम उठाएंगे दो कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है और 2 पीएफ से जुड़े हैं। एमएसएमई में डाला जाएगा।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम व लॉकडाउन योजना के लिए 20 हजार करोड़ का प्राविधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो क्षमता देश के बारे में विवरण देते हुए कहा कि आज प्रवासी मजदूरों के लिए होगी जो गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था आइये जानते हैं, वित्त मंत्री की आज की बड़ी घोषणा।

ग्रीन एण्ड कलीन संस्था 21 मार्च से अब तक ढाई लाख आबादी वाले शहर के 80 प्रतिशत क्षेत्र को कर चुकी है सैनिटाइज

डा. राजेश शस्त्राना,
एपिटर इन चीफ,

अनुकरणीय पहल



ग्रीन एण्ड कलीन संस्था ने 21 मार्च से नगर के गांधी चौक से सेनेटाइजेशन का जो कार्य आरम्भ किया था वह लगातार जारी है। संस्था ने छिड़काव के साथ आम लोगों को लॉक जाउन पालन के लिये लगातार सावधान भी किया। संख्या द्वाई लाख आबादी वाले शहर के 80 प्रतिशत क्षेत्र को सैनिटाइज कर चुकी है। संस्था में युवा अधिक संख्या में है कई अनुभवी अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं अन्य समाजसेवी लोगों का भी सहयोग संस्था को गिर रहा है।

संस्था में जगदूर दिवस के अवसर पर नगर परिषद के एक तो से यादा सफाई कर्मियों को सामूहिक रूप से सम्मानित किया। उनपर फूलों की वर्षा की एवं समान का चादर ओढ़ाया और टीका लगाकर उन्हें सम्मानित किया। वही संस्था के एक योद्धा अमरेंद्र सिंह ने कहा कि जहां सारे शहर की लोग घरों में बंद रह रहे हैं तो उस रिपोर्ट में हमारी सुरक्षा के लिए लिए कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं। वे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा लगे रहे हैं। दुर्सा समान में संस्था ने नार के सभी थाना के पुलिस को सामूहिक रूप से सम्मानित किया। सम्मानित होनेवाले में काफी संख्या में पुलिस आधिकारी और महिला पुलिस थे। वही संख्या ने तीसरे चरण के समान समारोह में मीडिया कर्मियों की सुधि ली। जिस मीडिया कर्मियों की सुधि न तो सरकार लेती है और न ही सामाजिक क्षेत्र के लोग लेते हैं जबकि पत्रकार इस क्षेत्र के दौर में अपने पत्रकारिता धर्म का लगातार पालन कर रहे हैं। पत्रकार आम लोगों को हर पल की जानकारी प्रिंट, टीवी और सोशल मीडिया के मध्यम से दे रहे हैं।

